

Title: Need to augment irrigation facilities in the country.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा घटकर 14.9 प्रतिशत रह गया है। कृषि अब सरकार की प्राथमिकता नहीं रही है। सरकार आम आदमी के खाद्यान्न सुरक्षा के लिए विशेषक लाने की बात कर रही है लेकिन खाद्यान्न सुरक्षा के लिए आवश्यक अनाज उत्पादन करने के लिए कृषि पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया जा रहा है। आज भी देश के अधिकतर हिस्सों में कृषि कार्य वर्षा जल पर निर्भर है। वर्षा जल पर कृषि निर्भरता से कृषि उत्पादन में अनिश्चितता असुरक्षा के कारण देश का कृषक हतोत्साहित हो रहा है। नेशनल सैम्पल सर्वे की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के कृषि से संबंधित 42 प्रतिशत युवा कृषि से विमुख होना चाहते हैं। कृषकों को लागत के अनुसार न्यूनतम समर्थन नहीं मिलने से स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है और किसान आत्महत्या पर उतारू हो रहे हैं। देश के किसानों की बढ़ावाली दूर करनी है तो पहले सिंचाई सुविधा देश के हर हिस्से में सुनिश्चित कराने की दिशा में काम करना होगा। आज पंजाब, हरियाणा में 94 प्रतिशत सिंचाई और महाराष्ट्र में केवल 19 प्रतिशत सिंचाई के आधार पर कृषकों को एक साथ नहीं समझा जाना चाहिए। यह सामाजिक विषमता की तरह सिंचाई विषमता का ज्वलंत उदाहरण है। सिंचाई कल उपलब्धता के आधार पर पंजाब, हरियाणा के किसान वर्ष में दो बार-तीन बार फसल लेते हैं और महाराष्ट्र सहित सिंचाई की कमी के कारण वर्षा जल पर निर्भर क्षेत्र के किसान एक ही फसल बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं। उनका प्रति हैक्टेयर उत्पादन भी कम होता है। इस स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार को अहम भूमिका निभानी चाहिए। आज राज्य सरकारों के पास संसाधन की कमी के कारण सिंचाई परियोजनाएं लंबित और अधूरी पड़ी हैं। उनका लागत मूल्य भी लगातार बढ़ रहा है। इसलिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के द्वारा ली गई सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी स्वयं ले, जिन राज्यों में सिंचाई का अनुशेष है, वहां की सभी सिंचाई परियोजनाओं को त्वरित सिंचाई परियोजना के अंतर्गत लाकर राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे और देश में सिंचाई की जो विषमता पैदा की गई है उसे समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़े। मैं सरकार से सिंचाई विषमता खत्म करने के लिए आवश्यक कदम और धनराशि आवंटित करने का आग्रह करता हूँ।